THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Government have been receiving data on radiation in foods from several national and international agencies like IAFA, WHO, USEPA, etc., after the Chernobyl accident. The radiation levels of food in India have remained much below the permissible levels even after the Chernobyl accident.

(b) Food items locally produced and imported are routinely checked for radiation by several countries including India. No item of food exported from India has been rejected on grounds of high radioactivity.

I. A. S. officers in Public Sector Undertaking

1473. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to post I. A. S. Officers in the Public Sector Undertakings on deputation basis;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what are the Public Sector Undertakings where I. A. S. Officers have been posted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir. Government have issued instructions that IAS and other Govt. officers can be appointed in Central Public Enterprises only on "immediate absorption" basis except in some undertakings specifically allowed to take these officers on deputation basis because of functional needs and on account of non-availability of persons with requisite background and professional skills. Officers belonging to the IAS, IPS and other Organised Services are however, posted as Chief Vigilance Officers in various Central Public Undertakings on deputation.

(c) As per the enclosed statement.

Statement

List of Public Sector Undertakings

1. FOOD CORPORATION OF INDIA.
2. NORTH EASTERN HANDLOOM & HANDICRAFTS CORPORATION
3. DAMODAR VALLEY CORPORATION
4. NATIONAL TEXTILES CORPORATION
5. POWER FINANCE CORPORATION
6. DELHI TRANSPORT CORPORATION
7. CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION LTD.
8. HANDICRAFTS & HANDLOOMS EXPORT CORPORATION OF INDIA LTD.
9. BENGAL IMMUNITY LIMITED
10. NATIONAL SEEDS CORPORATION
11. JUTE CORPORATION OF INDIA LTD.
12. EXPORT CREDIT & GUARANTEE CORPN. OF INDIA LTD.
13. NUCLEAR POWER CORPN. LTD.
14. INDUSTRIAL REFINANCE BANK OF INDIA

मध्य प्रदेश में किसानों की भूमि का अधिग्रहण

1474. **श्री अजीत जोगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदौर जिले की मऊ तहसील के कई गांवों में हजारों किसानों की भूमि का रक्षा

संस्थानों के लिए उपरिहार्य रूप से अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसानों को दिए जा रहे मुआवजे की अपर्याप्तता को लेकर किसानों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है; और

(ग) इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा तय किए गए मुआवजे की धनराशि पर रक्षा मंत्रालय के सहमत न होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) इंदौर जिले में बीरछा एवं हेमा में फील्ड फायरिंग रेंजों के लिए लगभग 5652 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन कलक्टर करता है। भूमि अर्जन कलक्टर ने इस संबंध में दो निर्णय लिए थे। इनमें से एक दो गांवों के लिए था और दूसरा सात गांवो के लिए था। दो गांवों के लिए दिए गए निर्णय का स्वीकार कर लिया गया है। सात गांवों के लिए दिए गए निर्णय का स्वीकार नही किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा निर्धारित दरों और रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा सिविल राजस्व प्राधिकारियों से एकत्र किए गए इसी प्रकार की भूमि की बिक्री संबंधी आंकड़ों के बीच काफी अधिक अन्तर है।

न्यायालय अवमानना कानून को संशोधित किया जाना

1475. **श्री अजीत जोगी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायालय के अवमानना संबंधी वर्तमान कानूनों का संशोधित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान कानून को उचित मानती है जिसके अन्तर्गत मानहानि के प्रकरणों में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सही तथ्य भी बचाव का उचित आधार नहीं माने जाते है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 14, 14(2) और धारा 19 में अवमाननकर्ता के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का उपबन्ध है अत: सरकार विद्यमान विधि को न्यायोचित मानती है।

Setting up of multi-member Election Commission

1476. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal from political parties regarding the setting up of multi-member Election Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ): (a) to (c) Some political parties have been giving expression to a suggestion that the Election Commission should be a multi-member body. The suggestions have appeared in the Press and Government's attention has also been drawn thereto. It is also a fact that such a proposal is under consideration of the Government as part of the proposals for electoral reforms formulated by the Election Commission. No final decision has been taken so far.